sulfation with Ministry of Finance to provide this facility to registrants at a high premium in foreign exchange in iuch a manner that the premium not only finances the cost of equipments but also generates surplus revenue for provision of public telephones in resettlement colonies, Jbuggi Jhopri Clusters, low income group **housing societies,** there is no proposal at present to import Cellular telephones.

(c) Against the Tender Enquiry of M/s, Motorola, C-DOT had submitted a bid in competition with other international firms for development of Cellular Application Plat form (CAP). Only a letter of intent has been signed last month between M/s. Motorola and C-DOT to enter into a con tractual relationship that will enable Mo torola Cellular Systems to work C-DOT switches through appropriate interfaces.

(d) No foreign exchange is involved in the above proposal.

8वीं योजना के दौरान दूर-संचार के आधुनिकीकरण पर व्यय

1432. **श्री राम अवधेश सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आठवीं योजना के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों के आधुनिकीकरण तथा आवश्यक अतिरिक्त उपस्करों के आयात पर कितना खर्चा होगा, तथा इस संबंध में विश्वभर में निविदायें आमंत्रित की गयी हैं ;

(ख) आठवीं योजना के दौरान दूरसंचार विभाग, वि विभाग तथा तार विभाग के विस्तार, विकास तथा आधुनिकीकरण पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ;

(ग) केन्द्रीय स्तर से क्षेत्रीय (राज्य) स्तर के उन ठेकेदारों का ब्यौरा क्या है जो एक करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये तक के उपकरण सप्लाई करेंगे;

(घ) उन भारतीय तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम क्या-क्या हैं जो 5 करोड़ रुपये से 15 करोड़ रुपये तक के तथा 15 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये तक के उपकरण सप्लाई करेंगे तथा उन्हें आवंटित किये गये काम/आवंटित किए जाने वाले प्रस्तावित काम का ब्यौरा क्या है;

(ङ) आठवीं योजना के दौरान संचार मंत्रालय द्वारा सम्पूर्ण आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू) : (क) 8वीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) के मसौदे में 19700 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय में 212 करोड़ रुपये की राशि दूरसंचार उपस्करों के आयात के लिए निर्धारित की गई है। सामान्य अभिप्राय, बहुत थोड़ी कमियों के लिए छोड़कर, तैयार उपस्करों के आयात न करने का है। इस वर्ष पूरे उपकरणों के लिए विश्व भर से निविदायें आमंत्रित की गई हैं।

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) के मसौदे के अनुसार तार उपकरण सहित दूरसंचार सेवाओं के विस्तार, विकास और आधुनिकीकरण के लिए 19700 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। इसमें से विभाग के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) में डाक सेवाओं के विस्तार, विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए 205 करोड़ रु० निर्धारित किये गये हैं।

(ग) और (घ) केन्द्र से क्षेत्रीय (राज्य) स्तर तक ठेकेदारों के ब्यौरे तैयार नहीं किये जा सकते क्योंकि खरीद खुली व्यावसायिक निविदाओं द्वारा की जाती है और ठेकेदारों के ब्यौरे भिन्न-भिन्न, निविदाओं में भिन्न-भिन्न हैं। अधिकांश आपूर्ति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों मै० आई०टी०आई० मै० एच०सी०एल०, मै० बी०ई०एल० आदि द्वारा की जाती है।

(ङ) 1990–95 की अवधि के दौरान दूरसंचार और डाक सेवाओं के पूर्ण आधुनिकीकरण और विस्तार योजना की लागत क्रमशः लगभग 19,700 करोड़ रुपये और 205 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

ऐतिहासिक पूजा स्थलों की यथापूर्व स्थिति बहाल रखना

1433. श्री मोहम्मद अकबल उर्फ मौलवी अकबल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में ऐतिहासिक स्थलों/मस्जिदों की 15 अगस्त, 1947 की यथा स्थिति बहाल रखने हेतु कोई कानून बनाने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक ऐसा कानून पास किये जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (ग) सरकार का इस विषय पर आगे विवाद समाप्त करने के उद्देश्य से इस बारे में बहुत जल्दी एक विधायन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित विधायन के ब्यौरों की जांच की जा रही है। हालांकि इस समय कोई निर्धारित तारीख नहीं बतायी जा सकती, फिर भी मामले पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है।

साम्प्रदायिक दंगे

1434. डा० अबरार अहमद : क्या गृह मंत्री 17 जुलाई, 1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 276 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में राज्य-वार कितने व्यक्तियों को साम्प्रदायिक दंगों के संबंध में गिरफ्तार किया गया ;

(ख) क्या उन भिड़न्तों में लिप्त कुछ लोगों को आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया था ; यदि हां, तो ऐसे लोगों की राज्यवार संख्या क्या है तथा उन लोगों के नाम क्या हैं ; और

(ग) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अधीन पिछले दो वर्षों में राजस्थान में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या क्या है तथा उनके नाम क्या हैं और वे कब से गिरफ्तार किये गये हैं ; छोड़े गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) उपलब्ध सूचना के आधार पर एक विवरण अनुपत्र के रूप में संलग्न है। [देखिए परिशिष्ट 159, अनुपत्र संख्या 39]

(ख) और (ग) लोक व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण यह कार्य संबंधित राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों का है कि वे आंतकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या और उनके नामों के बारे में सूचना रखें। इस मंत्रालय में ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।